भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 629

06 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः किसानों की औसत आय

629. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश के विभिन्न राज्यों में किसानों की औसत आय के बारे में कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वित्त वर्षों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में किसानों की आय का स्तर विश्व महामारी के पूर्व के स्तर से अधिक हो गया है या नहीं हुआ है;

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने विश्व महामारी से पूर्व के स्तर को पार कर लिया है और क्या कोई राज्य अभी भी पीछे चल रहे हैं;

(ङ) क्या इनमें से कुछ राज्यों के कृषि क्षेत्र में कमजोर सुधार के लिए कतिपय आर्थिक कारणों की पहचान की गई है; और

(च) देश में किसानों की आय को संतुलित रूप से दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (च): राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई 2018-जून 2019 तक के संदर्भ में एनएसएस के 77वें दौर (जनवरी 2019-दिसंबर 2019) के दौरान कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) आयोजित किया था। एनएसएसओ द्वारा कृषि वर्ष जुलाई 2012-जून 2013 के संदर्भ में एनएसएस 70वें दौर (जनवरी 2013-दिसंबर 2013) के दौरान भी इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया था। एसएएस के परिणाम के अनुसार, 2012-13 और 2018-19 के दौरान प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय निम्नानुसार।

अवधि	औसत मासिक आय (रुपये में)
2012-13 (70 वाँ दौर)	6,426
2018-19 (77 वाँ दौर)	10,218

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 576 एसएएस (70वां दौर-2013) और एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587, एसएएस (77वां दौर-2019), एमओएसपीआई।

सरकार ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसानों को उच्च आय उपलब्ध कराने के लिए कई नीतियों, सुधारों, विकासपरक कार्यक्रमों और योजनाओं को अपनाया और कार्यान्वित किया है। सरकार के निम्नलिखित प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए बजट में अभूतपूर्व वृद्धि के प्रावधान किए गए है:

1. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
3. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण
4. उत्पादन लागत से डेढ़ गुना पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करना
5. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना
6. पर ड्रॉप मोर क्रॉप
7. सूक्ष्म सिंचाई निधि
8. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना
9. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
10. कृषि मशीनीकरण
11. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना
12. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) विस्तार मंच की स्थापना
13. खाद्य तेल- ऑयल पाम के लिए राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ
14. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)
15. कृषि उपज रसद में सुधार, किसान रेल की शुरूआत।
16. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) - क्लस्टर विकास कार्यक्रम:
17. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इको सिस्टम का निर्माण
18. कृषि एवं संबद्ध कृषि जिन्सों के निर्यात में उपलब्धि
19. केंद्रीय क्षेत्र की योजना नमो ड्रोन दीदी।

उपर्युक्त प्रयासों से, पिछले पांच वर्षों में 4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करते हुए कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीवीए में वृद्धि हुई है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक पुस्तक जारी की है, जिसमें अपनी आय में दोगुना से भी अधिक वृद्धि करने वाले असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की कहानियाँ संकलित हैं।

*****